1	2	3	4	5	6
28.	Daman & Diu	0	1	28	29
29.	Delhi	0	62	• 138	200
30.	Lakshadweep	0	10	0	10
31.	Pondicherry	0	0	276	276
32,	Chandigarh	0	0	24	24
	TOTAL	56269	312473	10600921	1430663

Statement-II

State-wise allocation of funds in 1998-99 under accelerated rural water supply programme (RWSP)

SI. No.	State/UT	Allocation (Rs. in crore)
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	99.205
2.	Arunachal Pradesh	36.230
3.	Assam	61.200
4.	Bihar	117.685
5.	Goa	2.838
6.	Gujarat	58.605
7.	Haryana	21.909
8.	Himachal Pradesh	19.671
9.	Jammu & Kashmir	55.146
10.	Karnataka	91.774
11.	Kerala	46.735
12.	Madhya Pradesh	110.631
13.	Maharashtra	133.015
14.	Manipur	13.300
15.	Meghalaya	14.250
16.	Mizoram	10.180
17.	Nagaland	10.580
18.	Orissa	52.365
19.	Punjab	16.686
20.	Rajasthan	109.545
21.	Sikkim	4.340
22.	Tamil Nadu	79.225
23.	Tripura	12.530
24.	Uttar pradesh	186.879
25.	West Bengal	71.696
26.	A&N Islands	0.125
27.	D&N Haveli	0.125
28.	Delhi	0.050
29.	Lakshadweep	0.125
30.	Pondicherry	0.050
31.	Darnan & Diu	0.125
	TOTAL	1435-410

"कपार्ट" द्वारा स्वंय सेवी संस्थाओं को अनुदान दिया जाना

904. **श्री डी.वी.यादव**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान "कपार्ट" द्वारा स्वंय सेवी संस्थाओं को दिए गए कुल अनुदान का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या आबंटित धन के दुरूपयोग से संबंधित कोई मामले प्रकाश में आए हैं,और

(ग) यदि हां,तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं,यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) कपार्ट ने वर्ष 1997-98 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को 34.32 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्र हैं। (**नीचे देखिए**)

(ख) जी,हां।

(ग) कपार्ट ने सूचित किया है कि 25 स्वैच्छिक संगठनों,जिनके संबंध में निधियों के दुरूपयोग की जानकारी मिली हैं,को "आगे सहायता बंद" श्रेणी में रखा गया हैं।

विवरण

कपार्ट द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान मंजूर की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य	राशि(करोड़ रूपए)
1.	आंध्र प्रदेश	6.53
2.	असम	0.83
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.05

क्रम संख्या	राज्य	राशि (करोड़ रूपए)
4.	बिहार	4.40
5.	दिल्ली	0.68
6.	गुजरात	1.88
7.	हिमाचल प्रदेश	0.49
8.	हरियाणा	0.12
9.	जम्मू व कश्मीर	0.15
10.	कर्नाटक	1.90
11.	केरल	1.81
12.	मध्य प्रदेश	0.89
13.	मेघालय	0.13
14.	मिजोरम	0.03
15.	महाराष्ट्र	0.48
16.	मणिपुर	1.14
17.	नागालैंड	0.08
18.	उड़ीसा	1.32
19.	राजस्थान	0.69
20.	तमिलनाडु	3.64
21.	त्रिपुरा	0.10
22.	उत्तर प्रदेश	3.57
23.	पश्चिम बंगाल	3.41
कुल		34.32

परती भूमि को उपजाऊ बनाया जाना

905. **श्री राम मोहिन्दर सिंह**:

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में परती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक पूंजी निवेश हेतु निगमित क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की हैं;

(ख) यदि हां,तो क्या सरकार ने देश में परती भूमि की उपलब्धता के संबंध में कोई अनुमान लगाया हैं ;

(ग) यदि हां,तो देश में कुल कितनी परती भूमि है तथा संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;और

(घ) उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कुल कितने अतिरिक्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होने का अनुमान हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील): (क) कृषि मंत्रालय की भूमि आधारित तकनीकों का प्रयोग करके नौ स्तरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण की परिभाषा के अनुसार परती (बैरन) भूमि पर्वतीय,रेगिस्तानी और ऐसी भूमि शामिल है जिसे काफी अधिक लागत के बिना कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता हैं । राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी,हैदराबाद ने 1,250,000 पैमाने पर दूर संवेदी उपग्रह प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके भूमि उपयोग/भू-आच्छादित श्रेणियों के आभार पर परती भूमि का वर्गीकरण परती चट्टानी/पथरीली बंजर भूमि/ शीट रॉक क्षेत्र के रूप में किया हैं । देश में परती भूमि को उपजाऊ बनाये जाने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है । दूसरी और वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए बंजरभूमि विकास विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की निवेश संवर्धन योजना क्रियान्वित कर रहा हैं । विदेश संवर्धन योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों,पंचायतों,ग्राम समुदायों,किसानों आदि की वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए प्रयोक्ता उद्योगों तथा अन्य उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थाओं,बैंकों,निगमित निकायों से संसाधनों को सुलभ बनाना/आकृष्ट करना/प्रवाही बनाना/जुटाना हैं ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी,हैदराबाद ने देश में परती चट्टानी/पथरीली बंजर भूमि/शीट रॉक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 6.25 मिलियन हैक्टेयर होने की सूचना दी हैं । देश में परती भूमि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न हैं । (**नीचे देखिए**)

(घ) परती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया हैं।